# राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की 1010 करोड़ रुपये की कार्ययोजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्ष 2010-11 में क्रियान्वित होने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये 1010 करोड़ 74 लाख की कार्ययोजना का अनुमोदन राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यकारिणी समिति की छठवीं बैठक में किया गया है। मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये करीब 392 करोड़, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों के लिये 321 करोड़ सहित मलेरिया उन्मूलन, क्षय उन्मूलन, अंधत्व निवारण, कुष्ठ रोग उन्मूलन और अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यक्रमों के लिये वित्तीय प्रावधानों का अनुमोदन हुआ।

बैठक में निर्देश दिये कि नेम बेस्ड इन्फारमेंशन ट्रेकिंग सिस्टम "नाम आधारित जानकारी प्रणाली" के लिये भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर का उपयोग प्रदेश में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से भी किया जाये। इस प्रणाली के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व तथा प्रसवोत्तर परिचर्या और जाँच तथा बच्चों के टीकाकरण की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी। प्राप्त जानकारियां ग्राम स्तर पर एन.एन.एम और आशा कार्यकर्ता तक पहुँचाई जायेगी इससे महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस प्रणाली को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने के लिये विकासखंड स्तर पर कम्प्यूटर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये करीब 78 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि प्रदेश में 80.25 प्रतिशत प्रसव संस्थाओं में संपन्न किये जा रहे हैं।

राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान ग्वालियर में पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन ऑफ इंडिया के तकनीकी सहयोग से पब्लिक हेल्थ मैनेजमेन्ट विषय में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा कार्यक्रम अगस्त माह से शुरू किया जा रहा है। इस उद्देश्य से पब्लिक हेल्थ फाउण्डेशन ऑफ इंडिया और राज्य शासन के मध्य शीघ्र ही अनुबंध सम्पन्न हो रहा है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट डिप्लोमा कार्स में कुल 60 सीटें निर्धारित हैं। इनमें 50 सीटें चिकित्सक संवर्ग तथा 10 सीटें अन्य संवर्ग के लिये रहेंगी। बैठक में जानकारी दी गई कि आर.सी.एच. कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों को 2 वर्ष की सेवा उपरांत नियमित किये जाने एवं प्री-पीजी में प्रवेश हेतु इन सर्विस उम्मीदवार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव का शीघ्र क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला चिकित्सालयों में रोगियों की बेहतर भोजन व्यवस्था के लिये प्रदेश के सभी 50 जिला चिकित्सालयो में माड्यूलर किचन स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा 23 जिलों में डायटिशियन के पदों पर भी शीघ्र भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिये आगामी माह तक करीब तीन हजार प्रशिक्षित नर्सों की भर्ती का काम पूरा कर लिया जायेगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 62 नये पोषण पुनर्वास केन्द्र शुरू किये गये हैं तथा अब तक कुल 202 केन्द्र स्थापित हो चुके हैं जिनके माध्यम से 31831 कुपोषण ग्रस्त बच्चों को नियमित रूप से पोषण आहार प्रदान कर उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया गया है।

कार्यकारिणी समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में पुरुष नसबंदी को प्रोत्साहित करने तथा नसबंदी के लिये प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि में राज्य शासन की ओर से समुचित अंशदान हितग्राहियों को प्रदान करने के बारे में भी निर्देशित किया। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की प्रगति का ब्यौरा देते हुए बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में सभी आदिवासी बाहुल्य 89 विकासखंडों में 92 चलित अस्पताल संचालित हैं। इनके माध्यम से मार्च 2010 तक 28.18 लाख मरीजों का उपचार किया गया है। वर्ष 2010-11 में प्रदेश के 25 ऐसे विकासखंडों में जहां अनुसूचित जाति की आबादी अधिक है वहां भी चलित अस्पताल शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

**प्रस्तुति : देवेन्द्र जोशी**